{ खुद के लिए जीने वाले की ओर कोई ध्यान नहीं देता पर जब आप दूसरों के लिए जीना सीख लेते हैं तो वे आपके लिए जीते हैं - परमहंस योगानंद }

सम्पादकीय

दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में दावा हकीकत से कोसों दूर

दिल्ली सरकार की बहुप्रचारित सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की हालत ऐसी क्यों देखने में आ रही है कि किसी अस्पताल में दवाइयां नहीं हैं तो कहीं रुई जैसी बुनियादी जरूरत की चीजें भी मरीजों के तीमारदारों को बाहर से लानी पड़ रही हैं।

दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने शासन काल में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव करने और उससे व्यापक पैमाने पर जनता का हित सुनिश्चित करने के दावे बढ़-चढ़ कर किए हैं। मगर इन दोनों क्षेत्रों में जो तस्वीरें सार्वजनिक रूप से पेश की गई, उसकी जमीनी हकीकत वैसी ही नहीं रहीं।

जहां तक स्वास्थ्य के क्षेत्र का सवाल है, अस्पतालों की दशा सुधारने से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक आम लोगों की आसान पहुंच के लिहाज से 'मोहल्ला क्लीनिक' भी खोले गए। मगर व्यवहार में इसका अपेक्षित लाभ लोगों को नहीं मिल सका। इसके समांतर पिछले कुछ महीनों के दौरान दिल्ली के कुछ सरकारी अस्पतालों से जिस तरह दवाइयों और अन्य संसाधनों की कमी के कई मामले सामने आए, उससे यही पता चलता है कि एक तरह की अव्यवस्था पसर रही है, जिसका खमियाजा वहां पहुंचने वाले मरीजों को उठाना पड़ता है।

गौरतलब है कि द्वारका इलाके में बुधवार को दिल्ली सरकार के इंदिरा गांधी अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों को रुई बाहर से खरीद कर लाने को कहा गया। यह स्थिति अपने आप में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का सच बताने के लिए काफी है। एक उपलब्धि और 'माडल' के रूप में बहुप्रचारित सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की हालत ऐसी क्यों देखने में आ रही है कि किसी अस्पताल में दवाइयां नहीं हैं तो कहीं रुई जैसी सबसे बुनियादी जरूरत की चीजें भी मरीजों के तीमारदारों को बाहर से लानी पड़ रही हैं। कुछ समय पहले खुद उपराज्यपाल ने यहां के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिख कर दिल्ली सरकार के कामकाज और दावों पर सवाल उठाए थे। दिल्ली के कुछ अस्पतालों में दवाइयों की कमी से जूझने की भी कई खबरें आई। आरोप-प्रत्यारोप के बीच आखिर यह व्यवस्था सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है कि लोग जब किसी बीमारी का इलाज कराने दिल्ली के किसी अस्पताल में पहुंचें तो वहां चिकित्सक, जरूरी दवाइयां और अन्य बुनियादी संसाधन उपलब्ध हों? सिर्फ प्रचार और दावा करने से किसी सेवा में सुधार नहीं होता, बल्कि उसके लिए वास्तव में पहल करनी पड़ती है। अगर कोई अड़चन आए, संसाधनों की कमी पैदा हो तो उसका विकल्प निकालना पड़ता है, ताकि समस्या का समाधान निकले।

वि शे ष

विरासत टैक्स एवं निजी सम्पत्ति सर्वे पर संकट में घिरी कांग्रेस पार्टी

लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता बादशाह नहीं होता बल्कि साधारण मतदाता बादशाह होता है क्योंकि उसके ही एक वोट से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। मतदाता को जो मूर्ख समझते हैं उनसे बड़ा मूर्ख दूसरा नहीं होता। ऐसे तथाकथित बयानों से भारत में संसदीय प्रणाली का लोकतंत्र कभी भी प्रभावित नहीं होगा, वह सफल रहा है और रहेगा क्योंकि भारत के लोग अनपढ़ व गरीब हो सकते हैं मगर वे अज्ञानी या मूर्ख नहीं है। उनका व्यावहारिक ज्ञान बहुत मजबूत होता है और वे राजनीतिक दलों के भ्रम में नहीं आने वाले, गुमराह नहीं होने वाले।

■ **ललित गर्ग**

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जनता के बीच जिस तरह के मुद्दों को लेकर चर्चा में हैं, उनमें देश विकास से अधिक मुक्त की रेवड़िया बांटने या अतिश्योक्तिपूर्ण सुविधा देने की बातें हैं तो 'विरासत टैक्स' के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई को हड़पने के सुझाव है। ऐसी विरोधीभासी सोच एवं योजनाएं कांग्रेस की अपरिपक्व एवं स्वार्थप्रेरित राजनीति को ही उजागर करती है। इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष एवं राहुल गांधी के विश्वस्त सलाहकार सैम पित्रोदा ने चुनावी समर में अपने ताजा बयान में विरासत टैक्स की वकालत की है। उन्होंने अमेरिका में लागू इस टैक्स की पैरवी करते हुए भारत के लिये उपयोगी बताया। सैम ने अपने बयान पर विवाद बढ़ता देख सफाई दी है, तो कांग्रेस ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया है। लेकिन राजनीति की इन कुचालों एवं ऐसे बयानों में कांग्रेस का इरादा जनता की मेहनत की कमाई की संगठित लूट और वैध लूट ही नजर आता है।

सैम पित्रोदा के बयान में कांग्रेस की सोच एवं संकल्प ही नहीं दिखा बल्कि कांग्रेस की भावी योजनाओं की परतें भी खुली है। भले ही इस बयान ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हो, लेकिन जनता को मूर्ख समझ हर बार हंगामा खड़ा करना कांग्रेस की नीति एवं नियत रही है। सैम ऐसे ही विवादास्पद बयानों से पूर्व में भी चर्चा में रहे हैं।

अमेरिका में विरासत टैक्स जैसी अनेक स्थितियां एवं कानून हैं जो भारत में नहीं है क्योंकि हर देश की अपनी स्थितियां होती है। सैम के इस बयान ने इसलिए तूल पकड़ लिया, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लोगों की संपत्ति के सर्वे का वादा किया है। इसकी व्याख्या भाजपा पहले से ही इस रूप में कर रही है कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति का आकलन करके संपन्न-सक्षम लोगों की संपदा का एक हिस्सा लेने का इरादा रखती है। चूंकि सैम पित्रोदा का कथन कुछ इसी ओर संकेत करता दिख रहा था, इसलिए भाजपा ने नए सिरे से उनके बयान को मुद्दा बना दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तो कहा जब तक आप जीवित रहेंगे, तब तक कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी और जब जीवित नहीं रहेंगे, तब आप पर विरासत का बोझ लाद देगी।' कांग्रेस की लूट जिन्दगी के साथ भी और जिन्दगी के बाद भी कह कर मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह कह दिया कि यदि कांग्रेस वैसा कुछ करने का नहीं सोच रही है, जैसा सैम पित्रोदा कह रहे हैं तो वह अपने घोषणा पत्र से संपत्ति के सर्वेक्षण वाली बात हटाए।' निश्चित ही कांग्रेस की संपत्ति के सर्वेक्षण की बात में गहरे अर्थ, संदेह एवं शंकाएं निहित हैं। राजननेताओं के बयानों पर राजनीति होना लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन जनता के हितों पर आघात करना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतन्त्र में सतत् रूप से अमीर-गरीब का विमर्श चलता रहता है, गरीबों के हित की बात करके अधिसंख्य मतदाताओं को लुभाना राजनीतिक चतुराई है, लेकिन जनता को बांटना एवं अलग-अलग खेमों में खड़ा करना, लोकतंत्र को कमजोर करता है१। मगर भारत का मतदाता अब इतना सुविज्ञ एवं समझदार हैं कि वे राजनेताओं की मंशा को समझकर उस समय आगे बढ़कर नेतृत्व खुद संभाल लेते हैं जब नेतागण अपना पथ भूल जाते हैं। भारत के चुनावों का इतिहास इसका गवाह रहा है। इसलिए राजनैतिक विमर्श चाहे जितना गर्त में चला जाये मगर मतदाता की सूझबूझ, जागरूकता एवं विवेक कभी मंद नहीं पड़ती।

भले ही सैम पित्रोदा अमेरिका का उदाहरण देकर उस पर भारत में बहस की जरूरत जता रहे थे, लेकिन उन्हें गलत समय ऐसा उदाहरण नहीं देना चाहिए था, जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह भारत की परिस्थितियों के लिये सही न हो और जिसके विवाद का विषय बनने की भरी-पूरी संभावनाएं हो। यह तो कांग्रेस ही जाने कि वह संपत्ति के सर्वे के जरिये क्या हासिल करना चाहती है, लेकिन इससे इन्कार नहीं कि देश में आर्थिक असमानता कम करने की आवश्यकता है। इसके बाद भी इस आवश्यकता की पूर्ति न तो वामपंथी सोच वाले तौर-तरीकों से की जा सकती है और न ही उन उपायों से, जो समाज में विभाजन पैदा करें। जो भी निर्धन-वंचित हैं या सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके उत्थान की अतिरिक्त चिंता की जानी चाहिए, लेकिन बिना उनका जाति, मजहब देखे, बिना विभाजन की राजनीति को किये।

सैम पित्रोदा, राजनीति की दुनिया में यह नाम कोई नया नहीं है, कांग्रेस के शासन में तकनीकी एवं आधुनिक विकास के वे पुरोध रहे हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के सलाहकार रह चुके पित्रोदा इस समय राहुल के खास लोगों में से एक हैं। पित्रोदा अपने काम से कम अपने बयानों के चलते ज्यादा चर्चे में रहते हैं। उनके बयान अक्सर कांग्रेस के लिए भी सरदर्द बनते रहे हैं। पित्रोदा के अनेक बयान पहले भी विवाद एवं कांग्रेस के सिरदर्द की वजह बन चुके हैं। साल 2019 में ही उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। उन्हें अधिक से अधिक टैक्स देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मध्यमवर्गीय परिवार को रोजगार और अधिक अवसर मिलेंगे। इस बयान ने भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई थीं और पार्टी को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा था। पित्रोदा यहीं नहीं रुके, उन्होंने 2019 के ही पुलवामा हमले पर कहा था कि ऐसे हमले तो होते रहते हैं, मुंबई में भी हमला हुआ था। निश्चित ही कांग्रेस के शासन में ऐसे हमले एवं साम्प्रदायिक दंगे होते ही रहते थे। उन्होंने बालाकोट एयरस्ट्राइक ऑपरेशन पर सबूत मांगे थे।

सैम पित्रोदा के बयान एवं कांग्रेस के घोषणा पत्र के निजी सम्पत्ति सर्वे की बात में अवश्य ही रिश्ता है, जिसने पूरे देश के सामने कांग्रेस का मकसद स्पष्ट कर दिया है कि निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर वह इस धन को अपने वोट बैंक में बांटना चाहती है। ऐसी योजना यूपीए सरकार में तय भी हुई थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक और उसमें भी सबसे अधिक मुस्लिमों का है, उस प्रकार से कांग्रेस की यह मुसलमानों को लुभाने एवं उन्हें लाभ पहुंचाने की अघोषित चुनावी घोषणा है, इस तरह की घोषणाएं लोकतंत्र में सुशासन एवं राजनीति मूल्यों को धुंधलाने की कुचेष्टा ही कही जायेगी।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता बादशाह नहीं होता बल्कि साधारण मतदाता बादशाह होता है क्योंकि उसके ही एक वोट से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। मतदाता को जो मूर्ख समझते हैं उनसे बड़ा मूर्ख दूसरा नहीं होता। ऐसे तथाकथित बयानों से भारत में संसदीय प्रणाली का लोकतंत्र कभी भी प्रभावित नहीं होगा, वह सफल रहा है और रहेगा क्योंकि भारत के लोग अनपढ़ व गरीब हो सकते हैं मगर वे अज्ञानी या मूर्ख नहीं है। उनका व्यावहारिक ज्ञान बहुत मजबूत होता है और वे राजनीतिक दलों के भ्रम में नहीं आने वाले, गुमराह नहीं होने वाले। यह सच है कि जब से भारत में जातिवादी, क्षेत्रवादी, भाषावादी, वर्गवादी व सम्प्रदायवादी राजनीति का बोलबाला हुआ है तभी से राजनीति के विमर्श में गिरावट आनी शुरू हुई है, लेकिन इस गिरावट को संभालने के लिये मतदाता को अधिक परिपक्व एवं समझदार होने की अपेक्षा है।

प्रदेश

माइक्रोसॉफ्ट और बाइटएक्सएल के सहयोग से शुरू हुआ हैकएक्सीलरेट-2024

139 से अधिक टीमों ने हैकेथॉन के लिए पंजीकरण कराया था, जिसमें से 50 को चुना गया

मॉर्निंग न्यूज @ हैदराबाद। वैश्विक टेक्नोलॉजी लीडर माइक्रोसॉफ्ट और भारत के प्रमुख एडटेक प्लेटफॉर्म बाइटएक्सएल ने चैतन्य भारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक राष्ट्रव्यापी हैकेथॉन 'हैकएक्सीलरेट 2024' का उद्घाटन किया। 26-27 अप्रैल 2024 के बीच आयोजित होने वाले इस दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को उद्योग के लिए तैयार करने के लिए एआई के माध्यम से रचनात्मकता की भावना जगाने और समस्या-समाधान के कौशल में वृद्धि करना है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माइक्रोसॉफ्ट के प्रिंसिपल प्रॉडक्ट मैनेजर मणिदीप बिकिना, बाइटएक्सएल के सीएसओ और सह-संस्थापक चरण ताडेपल्ली और सीबीआईटी के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉ. सीवी नरसिम्हुलु की ओर से किया।

इस कार्यक्रम में भारत से विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के 2000 से अधिक बी.ई. और बी.टेक. छात्र वास्तविक जीवन की

समस्या-समाधान परियोजनाओं को क्रैक करने, प्रमुख सत्रों का लाभ उठाने और तकनीकी विशेषज्ञों से उद्योग संबंधी इनपुट को जुटाने के लिए यहां आए हैं। दो दिवसीय हैकेथॉन को देश भर में हैकएक्सीलरेट 2024 के माध्यम से इंजीनियरिंग शिक्षा और आईटी कौशल में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। हैकेथॉन देश के सभी कोनों से उभरते प्रौद्योगिकीविदों को अपनी प्रतिभा को दिखाने और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए नए समाधानों पर सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। छात्र कोडिंग, डिजाइनिंग और प्रोजेक्ट बिल्डिंग की 24घंटे के मैराथन में भाग लेने के लिए विशेष रूप से उत्साहित हैं, जहां वे एक संपूर्ण नजरिये और लक्ष्य के साथ कोडिंग करते हैं। यह हैकेथॉन प्रतिभागियों को विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने के दौरान अपने कौशल और रचनात्मकता की सीमाओं को आगे बढ़ाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। इनोवेशन को बढ़ावा देने और प्रतिभाओं को मार्गदर्शन दिए जाने के साथ हैकएक्सीलरेट 2024 का मकसद समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रौद्योगिकीविदों की अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना है।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2024

श्री अन्नपूर्णा रसोईयों में होगा गीले और सूखे कचरे का सेग्रीगेशन

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर। नगर निगम ग्रेटर की ओर से गीले व सूखे कचरे के सेग्रीगेशन के लिये निरन्तर प्रयास किए जा रहे है शुक्रवार को नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय स्थित श्री अन्नपूर्णा रसोई से

इसकी शुरुआत की गई। श्री अन्नपूर्णा रसोई में गीले व सूखे कचरे को अलग-अलग कर अतिरिक्त आयुक्त सीमा कुमार की ओर से हूपर में अलग-अलग डाला गया। अतिरिक्त आयुक्त ने आमजन से अपील की कि गीले व सूखे कचरे को अलग-अलग करें तथा उसकी कम्पोंस्टिग के भी आवश्यक रूप से प्रयास किए जाए। उपायुक्त स्वास्थ्य नवीन भारद्वाज ने बताया कि नगर निगम ग्रेटर की सभी श्री अन्नपूर्णा रसोई में नीले व हरे रंग के डस्टबिन रखवाये गये है जिससे गीले व सूखे कचरे को अलग-अलग किया जा सके तथा उन्हें पृथक-पृथक कर हूपर में डाला जाए।

जवाहर कला केन्द्र में फिर से खुलेगी राजस्थानी कलाकारों की गैलरी

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर। जवाहर कला केंद्र (जेकेके) में बनी स्फटिक आर्ट गैलेरी को अब परमानेंट खोलने की तैयारी हो गई है। अब इसे परमानेंट खोलने की तैयारी कर रहा है। वहीं, वरिष्ठ कलाकारों के विरोध के बाद एक विशेष कमेटी का भी गठन किया जा रहा है। इसके तहत जवाहर कला केन्द्र में संग्रह की गई कलाकृतियों की जांच की जाएगी। वरिष्ठ कलाकारों ने इस संग्रह से कुछ कलाकृतियों के गायब होने की जानकारी दी थी। जेकेके प्रशासन का कहना है कि स्फटिक को चार दिन के लिए ट्रायल बेस पर शुरू किया गया था। अब इसमें कुछ मेंटेनेंस का कार्य करने के बाद नियमित दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था भी अलग से की जाएगी। जेकेके के पास राजस्थान के कलाकारों के बेशकीमती कलेक्शन मौजूद है।

जांच करवाई जाएगी : जेकेके के वरिष्ठ लेखाधिकारी चेतन कुमार शर्मा ने बताया कि

जवाहर कला केन्द्र के कला संग्रह के प्रति कला प्रेमियों में विशेष रुचि है। ट्रायल बेसिस पर स्फटिक दीर्घा में कला संग्रह की 50 कलाकृतियां व 40 से अधिक पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई थी। इनमें लोक हस्तशिल्प कला जैसे मेटल वर्क, क्ले वर्क, वुड वर्क से जुड़ी कलाकृतियां और केन्द्र के कला शिविरों में तैयार पेंटिंग्स डिस्प्ले थी। निकट भविष्य में केन्द्र की ओर से कला संग्रह की प्रदर्शनी को निरंतर जारी रखने की योजना है।

ब्लू है पानी पानी पर किया जमकर डांस

चिलचिलाती गर्मी में नन्हें मुन्ने बच्चों ने की पूल पार्टी

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर। जयपुर के करतारपुरा स्थित किड्स पैराडाइज स्कूल में चिलचिलाती गर्मी में शुक्रवार को पूल पार्टी का आयोजन हुआ। जिसमें स्कूल की कक्षा प्री नर्सरी और नर्सरी के नन्हें मुन्ने बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों ने पूल पार्टी में जहां आज ब्लू है पानी पानी आदि गानों पर पानी के अंदर जमकर मस्ती की। पूल पार्टी के दौरान कुछ बच्चों ने रंग-बिरंगी स्विमिंग सूट पहनकर इसमें भाग लिया। बच्चों ने पूल पार्टी का जमकर लुफ्त उठाया।

स्कूल के डायरेक्टर महेंद्र हिंगोनिया ने बताया कि बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ अन्य

कार्यक्रमों में भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इससे बच्चों में मानसिक और शारीरिक दोनों का विकास होता है। पूल पार्टी के जरिए बच्चों को शिक्षा के साथ गर्मी से राहत दिलाने के लिए कक्षावार इस तरह का आयोजन होता है। टीचर प्रियंका शर्मा ने बताया कि बच्चों को तपती गर्मी से राहत दिलाने के लिए इस एक्टिविटी का आयोजन किया गया है।

मोतीलाल संघी की 149वीं जयन्ती मनाई

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर। श्री सन्मति पुस्तकालय के संस्थापक मा. मोतीलाल संघी की 149वीं जयन्ती शुक्रवार को मनाई गई। कार्यक्रम में अध्यक्ष विवेक काला, जस्टिस नगेन्द्र जैन, जस्टिस नरेन्द्र

जैन, डॉ. ज्ञानचन्द जैन, अरूण हाड़ा, विद्या अमित काला, कमला काला, प्रीति जैन, इन्दुबाला जैन, संदीप ठोलिया, हेमन्त हासुंका, डॉ. कोकिला जैन मानद मंत्री एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। प्रेमलता हासुंका, डॉ. पी.आर. मीना एवं करीब 60 विद्यार्थी जो कि अध्ययनरत है उपस्थित थे।